>

Title: Need to regularize the services of temporary employees working in Government Departments and Public Sector Undertakings.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे देश में लाखों ऐसे नौजवान साथी या कर्मचारी हैं, जो सालों से टेंपरेरी लगे हुए हैं और अभी तक कोई कारगर नीति उनके लिए नहीं बनायी गयी है। आपको यह जानकार ताज्जुब होगा कि तकरीबन 18-18 साल से उन लोगों को सरकारी नौकरियों में भी कैजुअल रखा गया है और जो प्राइवेट संस्थायें हैं, उनमें तो कैजुअल रखा ही गया है। इसका एक आंकड़ा मेरे पास है, जिसमें तकरीबन 33 परसेंट ऐसे हैं, जो कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। उनको जो तनख्वाह मिलती है, अगर उसे अर्बन एरिया में देखें तो जो परमानेंट हैं, उनको 365 रूपए मिलती है और जो कैजुअल हैं उनको 122 रूपए मिलती है, जो रूरल में परमानेंट हैं, उनको 232 रूपए मिलती है और कैजुअल वालों को सिर्फ 94 रूपए मिलते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आज साठ साल होने के बाद भी कोई ऐसी कारगर नीति नहीं बनायी गयी, जिसमें उनको अपने आप एक समय-सीमा के बाद परमानेंट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। उनके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है और वे बेरोजगार हो जाते हैं, उनको निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। 10-12 साल नौकरी पर रहने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत होती है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कोई ऐसी नीति बनाए कि एक समय-सीमा के बाद उनको परमानेंट कर दिया जाए, ताकि जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसका बेनेफिट उनको मिल सके।